

विचार

पुलिस स्टेशनों में सड़ते वाहनों की समस्या

भारत में अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में वाहन अक्सर महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कार, मॉटरसाइकिल, ट्रक या अन्य साधन अपराध के दृश्य का एक अभिन्न हिस्सा हो सकते हैं। पुलिस द्वारा इन वाहनों को जब्त कर लिया जाता है और साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किया जाता है। हालांकि, इन जब्त वाहनों का प्रबंधन और रखरखाव एक ऐसी समस्या बन चुका है, जो न केवल पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द है, बल्कि पर्यावरण, संसाधनों और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक गंभीर चुनौती बन गया है। पुलिस स्टेशनों और मालखानों में ये वाहन वर्षों तक सड़ते रहते हैं, जिससे न केवल जगह की कमी होती है, बल्कि यह व्यवस्था की नाकामी को भी उजागर करता है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की धारा 102 के तहत पुलिस को ऐसे वाहनों को जब्त करने का अधिकार है, जो अपराध से संबंधित हों। इन वाहनों को मालखाने या पुलिस स्टेशन के परिसर में रखा जाता है, जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। हालांकि, सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया अक्सर लंबी चलती है। कई मामलों में, सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं और इस दौरान जब्त वाहन पुलिस स्टेशनों में खड़े रहते हैं। बारिश, धूप और धूल के संपर्क में रहने के कारण ये वाहन खराब हो जाते हैं और धीरे-धीरे कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इससे भारत को हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नक्सान हो जाता है।

कई मामलों में, ये वाहन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं, जो शायद निर्दोष हों या जिनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिले। उदाहरण के लिए, एक ऑटो-रिक्षा चालक या टैक्सी ड्राइवर के लिए उसका वाहन उसकी आजीविका का मुख्य साधन होता है। जब ऐसे वाहन लंबे समय तक पुलिस हिस्सत में रहते हैं, तो मालिक की आथक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। यह सामाजिक असमानता को और बढ़ाता है कि क्योंकि अधिकांश प्रभावित लोग निम्न या मध्यम वर्ग से होते हैं। इसके अलावा, पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े वाहन अक्सर आस-पास के निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। ये वाहन सड़कों को अवरुद्ध करते हैं, पार्किंग की समस्या पैदा करते हैं और कई बार असामाजिक तत्वों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि वाहनों के महत्वपूर्ण हिस्से, जैसे बैटरी, टायर या इंजन के पुर्जे गारब हो जाते हैं। यह न केवल भ्रष्टाचार को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया को कमज़ोर करता है।

इस समस्या के समाधान के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। पहला कदम यह हो सकता है कि वाहनों की जब्ती और रिहाई की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया

अफ्रीकी देश माली में तीन भारतीयों के अपहरण के आतंकी वैश्विक मायने को ऐसे समझिए

कमलेश पांडे

अफ्रीकी देश माली में तीन भारतीयों के अपहरण के आतंकी मायने स्पष्ट हैं और साफ तौर पर भारत सरकार को आगाह करने वाले हैं। आखिर यह महज संयोग है या फिर कोई अभिनव प्रयोग, कि एक तरफ गत 1 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम अफ्रीका के देशों की यात्रा पर रवाना हुए, और दूसरी तरफ पश्चिमी अफ्रीका के ही पश्चिमी माली में गत 1 जुलाई को ही कई जगहों पर आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों के बाद तीन भारतीय नागरिकों को बंधक भी बना लिया गया है। कहना न होगा कि जिस तरह से इस बारदात में शक की सुई कुयात वैश्विक आतंकवादी संगठन अलकायदा समर्थित मुख्यौटा संगठन नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन यानि जेनआईएम की ओर घूम रही है, वह चिंता का विषय है।



बताया जाता है कि जेनआईएम वर्ष 2017 में अस्तित्व में तब आया था, जब इसने पश्चिम अफ्रीका में सक्रिय चार बड़े जिहादी गुटों- अंसार दिन, अल-मुगाबितुन, अल-कायदा इन द इस्लामिक मपरेब यानी एक्यूआईएम की साहेल बाच और मकना कर्तीबात मासिना ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की। चुंकि यह भी एक कट्टू इस्लामिक संगठन है, जिसका मकसद एक कट्टू इस्लामिक शासन की नींव रखना है। इसलिए इसी पर भारतीयों के अपहरण का शक है। इस अजीबोगरी अफ्रीकी आतंकी अपहरण की घटना के मामले स्पष्ट हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि भारत विरोधी अमेरिका-चीन-पाकिस्तान-ईरान की आतंकी पकड़ कितनी ज्यादा है। कारण कि इशारे के बिना भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के ठीक पहले ऐसी दुसराहसिन कार्रवाई करने की जुर्जती संगठन में ही नहीं सकती है। इसलिए भारत सरकार को सजग हो जाना चाहिए और ऐसी वारदातों के बाद त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया देने की युआइश तत्वाशी जानी चाहिए। अन्यथा सम्बन्धित देश के मिलीभाग से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह हमला कायेस में डायर्मेंट सीमेंट फैक्ट्री में हुआ, जहां हथियारबंद लोगों के एक समूह ने साइट में प्रवेश किया और

बहां कार्यरत मजदूरों का अपहरण कर लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय यानि एमईए के मुताबिक, पीडित इस फैक्ट्री के कर्मचारी थे और उन्हें जानबूझकर हिंसक बुसपैट के दौरान निशाना बनाया गया है। एमईए ने कहा है कि यह घटना 1 जुलाई को हुई, जब हीथ्यारबंद हमलावरों के एक समूह ने फैक्ट्री परिसर में एक कॉर्टिंगेड हमले किया था और तीन भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बना लिया। हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले के दिन ही जिस प्रकार से माली के कई हिस्सों में कॉर्डिनेटेड आतंकवादी हमले हुए, उससे संदेह की सुई सीधे अल-कायदा समर्थित संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन की तरफ जाती है। ऐसा इसलिए कि जेनआईएम ने उसे किया अब अस्तरे जैसे कायेस, डिवीली और सांडर में भी हमलों की जिम्मेदारी ली थी।

समझा जाता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के घातक प्रभावों के द्वारा से आतंकियों ने इस घटना की सीधी जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि इसमें ही भारतीयों का अपहरण किया गया था। यूं तो भारत सरकार ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। भारत सरकार ने माली सरकार से बंधकों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने

की मांग की है। बताया गया है कि भारतीय दूतावास बमाको में स्थानीय अधिकारियों और फैक्ट्री प्रबंधन के संपर्क में है। उसके द्वारा पीडितों के परिवारों को लगातार जानकारी दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन यानि जेनआईएम एक कट्टू इस्लामिक संगठन है, जिसका मकसद एक कट्टू इस्लामिक शासन की नींव रखना है। इंयाद अग घाली और अमादी कोप इस संगठन का नेतृत्व करते हैं। बताया गया है कि इंयाद एक दुआरें जातीय नेता है जबकि कूफा फुलानी, स्थानीय मुस्लिम समुदाय का प्रभावशाली इस्लामी उपदेशक है। इस प्रकार दोनों को घातक साझेदारी से पता चलता है कि जेनआईएम सिर्फ इस्लामिक कट्टूरा ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी रणनीति का हिस्सा बनाता है।

उल्लेखनीय है कि जेनआईएम ने खुद को अल-कायदा के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित किया है। इससे साफ है कि यह भी उसी तरह का खुराकाती संगठन है। समझा जाता है कि जब से अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम जगा है, तब से आतंकियों की चांदी हो गई है और अपना पुनः विस्तार कर रहे हैं। विशेषज्ञों द्वारा यह देखा गया है कि जेनआईएम ने विभिन्न इलाकों में इसके कानूनी विवरण का विवरण दिया है।

जानकारों के मुताबिक, जेनआईएम के पास इस समय तकरीबन 5-6 हजार लड़ाके हैं। इसकी संरचना काफी विविधित है, जिसकी वजह से ये अलग-अलग स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। यह संगठन अलकायदा का फैक्चाइज शैली में काम करता है। जिसका अधिकार्य यह हुआ कि विभिन्न इलाकों में इसके स्थानीय कमांडर स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं।

गैरितलब है कि जेनआईएम ने खुद को अल-कायदा के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित किया है। इससे आतंकियों की पहुंच हो गई है और अपना पुनः विस्तार कर रहा है। बल्कि यह भी उसी तरह का खुराकाती संगठन है। स्थानीय सरकारों की तानाशाह रवैये ने भी स्थिति को और ज्यादा खराब ही किया है। जेनआईएम ने लोगों के द्वारा याताया है और अपने प्रभाव का आतंकी विवरण किया है।

उल्लेखनीय है कि मई 2025 में इसने बुर्किना फासो के डिजीबो में हमला कर लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, जेनआईएम अब पश्चिमी माली से लेकर बेनिन, नाइजर और यहां तक कि नाइजीरिया की सीमा तक एक जिजाहादी बेल्ट्स बनाने में जुटा है। यह बेल्ट संगठन के नियंत्रण वाले इलाकों को जोड़ता है, जहां वह टैक्स वसूलने का साथ साथ शरीया कानून के तहत शासन करता है।

बताया जाता है कि अफ्रीका महादेश के विभिन्न देशों में अमेरिका, रूस, इंडिया, फ्रांस और अंतर्रिक्ष भूमिका को लेकर यहां नाराजी है। स्थानीय सरकारों की तानाशाह रवैये ने भी स्थिति को और ज्यादा खराब ही किया है। जेनआईएम ने लोगों के द्वारा याताया है और अपने प्रभाव का आतंकी विवरण दिया है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल वर

